

# **SUPPORTIVE DOCUMENTS**

**(Copies of Media, Punjab Govt. Letters,  
Pictures of activities)**

## घर में स्पैशल बेटी पैदा हुई और अमरजीत सिंह आनंद बन गए दिव्यांगों के मसीहा

अमरजीत सिंह आनंद का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 1984 के दंगों में कानपुर से विस्थापित होकर जालंधर में बसे अमरजीत आनंद एक मिसाल बन गए हैं। स्पैशल बच्चों की केयर को लेकर शुरू किया सफर आज दिव्यांगों के लिए एक मसीहा के रूप में सामने है। चुनाव दौरान अगर दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं तो इसमें आनंद की बड़ी भूमिका है।

कानपुर में आर्मी कांटैक्टर मनोहर लाल आनंद के घर 1955 में जन्मे अमरजीत सिंह आनंद की जिंदगी का सफर बड़े उत्तर-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने शिक्षा-दीक्षा कानपुर में पूरी की। 1984 में दंगे भड़के तो पूरे देश में सिखों पर अत्याचार हुए, ऐसे में पिता परिवार के साथ जालंधर आ गए। जालंधर में अमरजीत सिंह आनंद के घर एक बच्ची ने जन्म लिया जो स्पैशल (दिव्यांग) थी। ऐसे बच्चे की देखरेख बारे उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में एक अच्छे पेरैंट्स बनने के लिए उन्होंने इसके लिए जब जानने की कोशिश की तो, उन्हें इसे हासिल करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके लिए जागरूकता ही नहीं थी, ऐसे में उन्होंने ऐसे पेरैंट्स को जागरूक करने का बीड़ा। उठाया और एक स्वयंसेवी संस्था चानन एसेसिएशन फार एमआर चिल्ड्रन का गठन किया। इसका विस्तार उन्होंने धीरे-धीरे पूरे पंजाब में किया और लोगों को जागरूक

किया। आज 15 जिलों में ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते गए और फिर दिव्यांगों के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। 2001 में स्पैशल ओलंपिक पंजाब चैप्टर के साथ जुड़े और इन बच्चों के हकों के लिए लड़ाई शुरू की। ऐसे बच्चे ओलंपिक में मैडल लेकर आते थे, उनके लिए कोई

सुविधा नहीं थी, इसके लिए जिला स्तर पर आवाज बने। इन बच्चों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान दिलाया। इन बच्चों के स्पैशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी सम्मान दिलाया, जिससे ऐसे बच्चों की गाइडेंस उनकी देखभाल को लेकर फैली भ्रांतियां खत्म हुईं और उनकी बेहतर देखभाल का विकल्प खुला। ओलंपिक में ऐसे बच्चों की तैयारी करने में ज्यादा मदद मिली।

सूबे में सरकार की नजर में डिसेबिलिटी कहीं थी ही नहीं, दिव्यांगों को सरकार से कोई तबज्जो नहीं मिलती थी। ऐसे में उनके हकों के लिए लड़े। नैशनल लैवल पर सभी डिसेबिलिटी फोरम के साथ जुड़े और ट्रेनिंग लेकर दिव्यांगों की जनगणना 2001 के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी। पंजाब में डिसेबिलिटी सैक्टर की गणना के लिए काम किया। स्पैशल ट्रेनिंग लेकर जनगणना करने वाले स्टाफ को ट्रेंड किया, फिर 2011

में जनगणना हुई तब दिव्यांगों का डाटा ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आया। इसी क्रम में 2007 में हुए नगर निगम चुनाव में स्टेट कोर्डीनेटर के तौर पर काम किया और डिसेबल लोगों को वोट कॉस्ट के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिक एंड ड्रॉप, व्हील चेयर इत्यादि तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं। अब तो यह एक एक्ट ही बन चुका है कि डिसेबल कैटागरी के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं।

इस दौरान राइट ऑफ पीपल्स डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बनने से लेकर बिल पारित होने तक पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। नाल्सर गूनिवर्सिटी हैदराबाद ने यह एक्ट ड्राफ्ट किया था। इस पर 6 साल तक चर्चा और गहन रिसर्च हुई थी, इसमें आनंद ने अहम भूमिका निभाई थी। यूएनओ के पार्ट यूनाइटेड नेशन कंवैशन फॉर राइट ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटी (यूएनसीआरपीडी) के तहत 114 देशों ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे। इन देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस एक्ट को लेकर सहमती जताई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इस एक्ट को लेकर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 9 साल बाद यह एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट के तहत जन्म से ही जो बच्चा दिव्यांग है उसे इस एक्ट के तहत जन्म, हैल्थ, एजुकेशन, स्किल डिवैल्पमेंट, इम्पावरमेंट तथा बाकी हकों को लेकर तमाम हक दिए गए हैं।

### इन अवार्ड्स से किया जा चुका है सम्मानित

- लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 (डाउन सिंड्रोम फेडरेशन इंडिया)
- भाई धनैया सेवा अवार्ड 2019 (सिख सेवक इंटरनेशनल यूके)
- अन संग हीरो 2015 अवार्ड (बिग एफएम)
- पंजाब स्टेट डिसेबिलिटी अवार्ड 2015
- लिओनार्ड कैशाहायर अवार्ड 2015 (चंडीगढ़)
- डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल अवार्ड 2015 (यूके)
- अशोक नैशनल अवार्ड 2015 (पटना)
- भाई धनैया सेवा अवार्ड 2013 (जालंधर)

### इन संस्थाओं का किया प्रतिनिधित्व

- चानन एसेसिएशन फार एमआर चिल्ड्रन प्रधान
- डिस्ट्रूक्ट स्पैशल ओलंपिक एसेसिएशन के चेयरमैन
- स्टेट फेडरेशन ऑफ पेरैंट्स ऑफ इंटेलैक्चुअल डिसेबिलिटी के प्रधान
- दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ 'परिवार' के सदस्य
- डाउन सिंड्रोम एसेसिएशन के पंजाब के प्रधान
- स्पैशल ओलंपिक एसेसिएशन पंजाब के वाइस प्रैसीडेंट
- कंट्री रिप्रेजेंटिव मोजेक डाउन सिंड्रोम यूएसए के सदस्य
- एशिया पैसेफिक डाउन सिंड्रोम सिंगापुर के सदस्य
- एक्सपर्ट मैंबर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड दिव्यांगजन (पंजाब सरकार)
- एक्सपर्ट मैंबर डिस्ट्रूक्ट एडवाइजरी बोर्ड दिव्यांगजन
- मैंबर लोकल लैवल कमेटी जालंधर, कफ्पुरथला, नवाशहर
- डिस्ट्रूक्ट चाइल्ड वैल्फेयर कमेटी के मैंबर

प्रस्तुति : राजेश योगी

मोबाइल : 098032-00078

ई-मेल yoggi2k123@gmail.com

**जिनसे है  
जालंधर**

अमरजीत सिंह आनंद



# स्पेशल परिवारों में चान्नण फैला रहे अमरजीत



वंदना गालिया बाती, जालधर

**सरकारी कार्यालयों में लोगों को अपने काम को करवाने में बहुत मुश्किल का समान करना पड़ता है।**  
सरकारी विभागों में तो चाहिए कि आने वाले लोगों का कार्य जल्द किया जाए। बार-बार कागजों की कमी निकालने की बजाय से कम समय में कार्य पूरा करना चाहिए, जिससे लोगों को बार-बार चक्कर न लगाना पड़े।  
-एडवोकेट नवदेव दूर, पूर्व चेयरमैन पंजाब व हरियाणा बार कॉर्सिल

सरकारी कार्यालयों में लोगों

को अपने काम को करवाने में

बहुत मुश्किल का समान करना

पड़ता है।

सरकारी विभागों

में तो चाहिए कि

आने वाले लोगों

का कार्य जल्द किया जाए। बार-बार

कागजों की कमी निकालने की बजाय

एक बार में सभी जनकारी देकर कम

से कम समय में कार्य पूरा करना

चाहिए, जिससे लोगों को बार-बार

चक्कर न लगाना पड़े।

-एडवोकेट नवदेव दूर, पूर्व चेयरमैन

पंजाब व हरियाणा बार कॉर्सिल

पंजाब की 30 वर्षीय बेटी जसजीत

कीर भी एक स्पेशल चाइर्ड है, जिस

वह अपनी प्रेरणा मानते हैं। वह कहते हैं

- किसी अन्य रूप में दिव्यांग (नेत्रहीन,

मृक, या बधि आदि) होने पर, व्यक्ति

स्पेशल बच्चों को अधिकार दिलाने को कर रहे संघर्ष

• स्पेशल बच्चों को अधिकार दिलाने को कर रहे संघर्ष

अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ सकता है, लेकिन मानसिक सुनीतियां खोल रहे बच्चे (मानसिक सम्बन्धों में जोड़ने व उनके परिवारों में जागरूकता और खुशियों का प्रकाश फैलाने के उनके अधक प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है।

आनंद की 30 वर्षीय बेटी जसजीत

कीर भी एक स्पेशल चाइर्ड है, जिस

वह अपनी प्रेरणा मानते हैं। वह कहते हैं

- किसी अन्य रूप में दिव्यांग (नेत्रहीन,

मृक, या बधि आदि) होने पर, व्यक्ति

मैंने 'चान्नण' नामक संस्था शुरू की

ताकि ऐसे बच्चों के अधिकारों को

एक मंच मिल सके। आज इस संस्था से

300 से अधिक लोग जुड़ हुए हैं।

हालांकि मात्र जालधर में ही 2500 से

ज्यादा स्पेशल बच्चे हैं। उनके बाद

ज्यादा परेंट्स या किसी अन्य को ही करने

परेंट्स या किसी अन्य को ही करने

पड़ते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए

मैंने 'परिवार' को जोड़ा ताकि

उनके स्पेशल बच्चों को राष्ट्रीय व

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

सरकार नड़ी बात यह है कि उन्हें आनंद

स्पेशल बच्चे के कारण हीन भावना से

उपर कर उनके सामाजिक जीवन के लिए

प्रेरित किया जाता है। 2007 में नेशनल

काउंसिल के कार्यकारी सदस्य के रूप

पंजाब का

प्रतिनिधित्व

सभानंदने बले

आनंद के

2013 में

'परिवार' संस्था

के उत्तर भेंत का

उपायक

बनाया गया।

## अमरजीत सिंह आनंद की उपलब्धिया

- » 2015 में शुरू की संस्था डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल द्वारा विवेद भर से बुने गए बार रिटर्निंग में आनंद एक मात्र भारतीय थे।
- » 2015
- » समर्पण पट्टन (विहार) द्वारा 2015 का भाई पहेंचा सेवा अवार्ड 2013 आशोक नेशनल अवार्ड

## प्रतिनिधित्व

- » 'परिवार' संस्था- उपायक
- » डाउन सिंड्रोम एसो. पंजाब के अध्यक्ष
- » 'चान्नण' एसोसिएशन पॉर्ट मैटली रिटार्डिंगिल्डन के अध्यक्ष
- » स्पेशल ओलंपिक्स (पंजाब वेटर)
- » के उपायक
- » पश्चिमांश यूप्रसाप में भारत के प्रतिनिधि
- » नेशनलट्रस्ट की कैम्प बढ़ावे के लिए पंजाब के ऑफिनेटर मोनोहास दिए गए।



अमरजीत सिंह आनंद

84

From

No. 27884 Gaz.II(2-G)

To

The Registrar General,  
Punjab and Haryana High Court,  
Chandigarh.

The Additional Chief Secretary,  
Government of Punjab,  
Department of Home Affairs and Justice,  
Chandigarh.

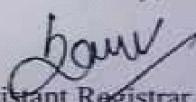
Dated: Chandigarh; the 17/11/17

**Subject :** Specifying Special Court under section 84 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.  
Sir,

I am directed by Hon'ble the Chief Justice to refer letter No.1/1/2017/3DC-1063661/1 dated 13.9.2017 (copy enclosed) of the Special Secretary, Government of Punjab, Department of Social Security and Women & Child Development and to request you to specify the Court of 2<sup>nd</sup> Additional Sessions Judge, and if there is only one Court of Additional Sessions Judge, then 1st Additional Sessions Judge in each district to be a Special Court under section 84 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, to try the offences under this Act.

You are, therefore, requested to issue necessary notification in this regard, at the earliest.

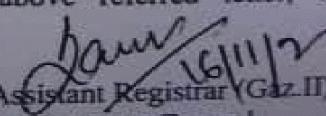
Yours faithfully,

  
Assistant Registrar (Gaz.II)  
for Registrar General

Encl: As above

Endst. No. 27885 Gaz.II(2-G) dated 17/11/17.

Copy is forwarded to the Special Secretary, Government of Punjab, Department of Social Security and Women & Child Development (Disability Branch) with reference to the above referred letter, for information and necessary action.

  
Assistant Registrar (Gaz.II)  
for Registrar General

o/c

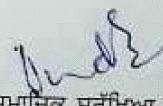
ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

1. ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਚੀਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
2. ਸਿਵਲ ਹਸਤਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਿਟਰਿਸਟ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੌਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
4. ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਜਲੰਧਰ
5. ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕਡਰੀ), ਜਲੰਧਰ
6. ਜਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ
7. ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ
8. ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ  
ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਟ, ਚਾਨਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਮ.ਆਰ.ਚਿਲਡਰਨ,  
ਜਲੰਧਰ।
9. ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਟਿਰੈਕਟਰ,  
ਕਿਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ।  
16 ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਲੇਨ ਨੰ: 1, ਵਡਾਲਾ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਰੋਡ  
ਜਲੰਧਰ।

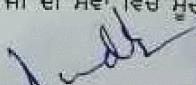
ਨੰ: ਜਸਸਾ/ਜ/2019/ 1510-1518 ਮਿਤੀ 15-09-2019  
ਵਿਸ਼ਾ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 17-09-2019 ਨੂੰ 12.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

  
ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ  
ਜਲੰਧਰ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕੜਣ ਨੰ: ..... 1519 ..... ਮਿਤੀ ..... 15-09-2019

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ  
ਅਗਲੇਰੀ ਧੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।

  
ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ  
ਜਲੰਧਰ।

## Office of the Deputy commissioner Jalandhar

Order

Under Section 72 of right of Persons with Disability act 2016 and 22 of rights of persons with disability rules 2019 the District Level Committee on Disability is constitute as given below:-

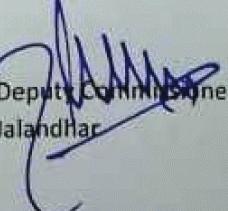
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Deputy Commissioner   | Chairman         |
| 2. Civil Surgeon, Jalandhar  | Member           |
| 3. Pshychiarist Civil Hospital, Jalandhar  | Member           |
| 4. Sh. Vivek Joshi, Advocate   | Member           |
| 5. District Education Officer (S)Jalandhar   | Member           |
| 6. District Education Officer(E) Jalandhar   | Member           |
| 7. District Transport Officer,Jalandhar  | Member           |
| 8. Secretary District Red Cross Society,Jalandhar  | Member           |
| 9. Sh. Amarjit Singh Anand<br>President, Chanan Association for M.R.Children<br>Jalandhar  | Member           |
| 10. Sh. Kuldip Singh, Associate Director<br>Krishi Vigian Kendra, Nurmahal<br>16 friends Colony, Lane No.1,Mithapur Road,Jalandhar | Member           |
| 11. District Social Security Officer, Jalandhar  | Member Secretary |

  
Deputy Commissioner  
Jalandhar

Endst. No. 1499-1509 Dated 15-09-2019

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. The Director Social Security, Women and Child Development Department, Punjab,Chandigarh.
2. Civil Surgeon, Jalandhar
3. Pshychiarist Civil Hospital, Jalandhar
4. Sh. Vivek Joshi, Advocate
5. District Education Officer (S)Jalandhar
6. District Education Officer(E) Jalandhar
7. District Transport Officer,Jalandhar
8. Secretary District Red Cross Society,Jalandhar
9. Sh. Amarjit Singh Anand,President, Chanan Association for M.R.Children,Jalandhar
10. Sh. Kuldip Singh, Associate Director,Krishi Vigian Kendra, Nurmahal  
16 friends Colony, Lane No.1,Mithapur Road,Jalandhar
11. Disstrict Social Security Officer, Jalandhr

  
Deputy Commissioner  
Jalandhar

## Lok Sabha Elections 2019: Over 68,000 registered, but official says there are many more

Data sourced from the office of Punjab chief electoral officer (CEO) shows that 68,551 PWD voters were registered till January 31 this year. Of these, 9,000 have registered so far in Jalandhar and 4,723 in Nawanshahr district.



Amarjit Singh Anand, expert member, state Divyang Advisory Board, said that the number of PWD voters is much more and an extensive awareness drive is required at the grassroots level.

For the upcoming Lok Sabha elections, the differently-abled have for the first time been registered as 'Person with Disability' (PWD) voters. But while Punjab has registered 68,551 such voters across all 22 districts, a member of the Divyang Advisory Board believes that the actual number is much higher.

Data sourced from the office of Punjab chief electoral officer (CEO) shows that 68,551 PWD voters were registered till January 31 this year. Of these, 9,000 have registered so far in Jalandhar and 4,723 in Nawanshahr district. Awareness campaigns including seminars and programmes under the Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) are being held across the state.

Speaking to The Indian Express, Amarjit Singh Anand, expert member, state Divyang Advisory Board, said that the number of PWD voters is much more and an extensive awareness drive is required at the grassroots level especially in rural areas, so more of them register.

Anand further said that according to a 2011 census, Punjab's population was 2.77 crore and the percentage of disabled was 2.64% of the population, which by now would have gone up to around 5% of the present population. "Even people with mental disabilities are eligible for voting if they are able to take their own decisions in other activities as there are different categories for that too," he said, adding that though registration of PWD voters ended in January, 'marking' of such voters will continue till April 19 (which means that disabled voters who have registered as general voters will be marked under the 'PWD' category so they get the facilities).

## Punjab: Audit of PWD booths reveals unsuitable ramps in rural areas

The audit is being conducted under the leadership Divyang Board member Amarjit Singh Anand, who has been appointed the state coordinator for this drive.



(Representational image)

The initial state-wide physical audit of polling booths by Divyang Icons — people with disabilities associated with the State Divyang Advisory Board — has revealed that nearly 30 per cent of booths in the Punjab designated for Persons With Disability (PWDs) have unsuitable or damaged wheelchair ramps, while others lack western-style toilet seats.

The audit is being conducted under the leadership Divyang Board member Amarjit Singh Anand, who has been appointed the state coordinator for this drive.

The final audit report will be presented to CEO, Punjab on May 4. Most issues have been reported from booths in the state's rural belt.

There are over 10,000 such booths across state designated for disabled persons out of total 23, 213 polling station.

"In the audit report, we have been checking wheelchair ramps, tables inside the booth, light, backup, drinking water, toilets etc.,," said a district coordinators from Majha region, adding that around 30 per cent booths need to be set right.

In Jalandhar, there are over 800 such booths out of total 1863 polling stations. Jalandhar coordinator Kaushly said that she has 236 booths in Phillaur area under her, out of which 105 she has already audited physically.

"I found that at several booths the ramp was not up to the mark, very steep and it did not begin from the main gate of the polling booth," she said, adding that even there is no English toilet at several booths and at some places toilets seats are high.

"These things can be set right as per the needs of the disabled persons," she said.

State coordinator Amarjit Singh Anand said: "This is the first time that people with disabilities have been engaged to do this audit in Punjab. We are getting the support from district administration too and will submit the report by May 4 so that the required rectification on certain places can be done before the polling day."

Inderjit Nandan, who is working as district Hoshiarpur coordinator, said that the election commission has been serious about PWD voters which is encouraging them to come out and vote.

# Independent charge eludes Disabilities Commissioner

**APARNA BANERJI**

TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, DECEMBER 2

Two years after the Parliament passed the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the state is yet to appoint an independent Commissioner for Disabilities, who is saddled with three other portfolios.

Commissioner for Disabilities Kumar Rahul is also the Secretary-cum-Director, Mining, and Secretary, Home Affairs, Justice and Jail. He was appointed in February. Before him, the post was vacant for several months.

Disability activists demand an independent Commissioner for Disabilities as they claim their grievances go unaddressed.

As per the 2011 Census, the state has 6.54 lakh persons with disabilities.

The state government is yet to notify policies to implement the 2016 Act.

Amarjit Singh Anand, a member of the Punjab State Advisory Board for Disabilities, said: "The Commissioner is pre-occupied with other portfolios at the cost of the disability sector. Until the policies for the disabled are notified, the Act can't be implemented. The state needs an independent Commission-

## ON CRUTCHES

- Commissioner for Disabilities holds three other portfolios
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, yet to be notified
- No disability Census in state since 2011
- No meet of the advisory board since the formation of the Congress government
- Disabled pension disbursement held up for more than six months

**6.54 LAKH**

DISABLED PERSONS IN STATE  
(2011 Census)

er for Disabilities for that."

He cited a few unaddressed issues: non-disbursal of pension for disabled persons for more than six months and no meetings of the advisory board ever since the Congress came to power. "In the name of a meeting, the advisory board had organised an introductory session with disability activists," Anand said.

Disability activist Vivek Joshi said, "I had sent repeated complaints to the Commissioner on harassment of disabled persons, but none was addressed. Every time we call, he is

busy or in a meeting. I complained about disability students not allowed to appear for their exams and mistreatment meted out to me by Air India staff. This is not all. The 2011 Census data has not been revised."

Minister for Social Security Aruna Chaudhary said, "Several officials have been sent to Chhattisgarh for the Assembly elections. Some of them will return on December 17, after which policy issues of the disability sector will be taken up. The state will get an independent Commissioner for Disability within a few months. This will be done before the code of conduct for the 2019 General Election is enforced. Anganwari workers will be deployed to collect data on persons with disabilities."

Commissioner for Disabilities Kumar Rahul dismissed the view that the additional portfolios were affecting his work. "I have been regularly responding to grievances. As for students not allowed to take the exam, we did intervene, but we will look into the matter as to why the issue was not addressed. Other issues will be addressed once the policy is notified. The government is working on that."

# मंदबुद्धि बच्चों की 'बुद्धि' बाने आनंद

सुक्रेत, जालंधर

जालंधर रेली स्टेशन के बाहर एक मंदबुद्धि महिला पूर्म रही थी। वहों छाड़े हुई युवकों ने उसे देखा। और हैबानियत पर उत्त आए। इससे पहले कि वह इस्पानियत व महिला की इन्जत को तार-तार करते, वहों से गुजर रहे। एक व्यक्ति ने उक्का गेका और उस महिला को वहां से ले गए। काफी प्रयास के पश्चात उस महिला को उन्होंने पुलिस की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जबकि उस महिला के परिजन मिलने के बावजूद उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। यह व्यक्ति और विकलाग हैं, वह अपनी बात किसी न किसी नहीं, बल्कि चानन एसोसिएशन फार मेटली रियर्ड चिल्ड्रन के प्रथम अमरीकी मेटिकल मटिफिकेट बनाते, रखते कन्सेन्शन, सिंह आनंद थे, जो पिछले 16 वर्ष से ऐसे खेल में यशस्म नहीं हैं। इसलिए उनकी सहा-बच्चों की बुद्धि बने हुए हैं जो मंदबुद्धि हैं। ऐसे बच्चों की बात बनाने के लिए प्रयासरत मिलता है, हेत्य इस्पानेस खीम 'निमया' का रख्य में 1500 रुपये प्रतिमाह है।

इतने सालों में उनको सरकार की तरफ से तो कोई सहाय नहीं मिला, पर बेसहायों का सहाय बनकर उन्होंने स्पान में एक मंदबुद्धि वालों की तरफ से उनको सहायता न मिलना है। उन्होंने कहा कि अपना दृष्टर बनाने के लिए तो सरकार के पास जमीन है, पर शेल्टर होम के लिए जमीन नहीं है। उनकी सस्था के पास इतना भैसा नहीं है कि वह जमान ले सके और सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि उनकी सस्था हर यात्रा लोगों में जागरूकता लाने के लिए 'बढ़ते कदम' कार्यक्रम चलाती है। कार्यक्रम के जारी लोगों में उनकी जागरूकता पैदा की जाती है कि मंदबुद्धि बच्चों को भी समाज में हक मिलना चाहिए। स्पेशल ओलिपिक्स भी काकाएं जाते हैं जिनमें ऐसे बच्चे ही हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम 350 मीटिंग में परिवार या घरी है। देशभर में परिवार 350 मीटिंग, बींधुर या यही काम कर रही है। उनकी सस्था मेटिंग वन्ड बच्चों के लिए सरकार एक हेल्थ के तहत मंदबुद्धि बच्चों के लिए, कितना सोचती है उसका उदाहरण यह है कि प्रथम अमरीकी नहीं तरह से अपनी बात मेटिकल मटिफिकेट बनाते, रखते कन्सेन्शन, सिंह आनंद थे, जो पिछले 16 वर्ष से ऐसे खेल में यशस्म नहीं हैं। इसलिए उनकी सहा-बच्चों की बुद्धि बने हुए हैं जो मंदबुद्धि हैं।

**सराहनीय**

- 16 वर्ष से मंदबुद्धि बच्चों के लिए चला है संस्था



प्रयास दिलवाने का प्रयास करती है। अमरीत सिंह आनंद ने बताया कि उनकी रह में सबसे बड़ा रोड़ा प्राजा ब सरकार की तरफ से सब्बायता न मिलता है। उन्होंने कहा कि अपना दृष्टर बनाने के लिए तो सरकार के पास जमीन है, पर शेल्टर होम के लिए जमीन नहीं है। उनकी सस्था के पास इतना भैसा नहीं है कि वह जमान ले सके और सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि उनकी सस्था हर यात्रा लोगों में जागरूकता लाने के लिए 'बढ़ते कदम' कार्यक्रम चलाती है। कार्यक्रम के जारी लोगों में उनकी जागरूकता पैदा की जाती है कि मंदबुद्धि बच्चों को भी समाज में हक मिलना चाहिए। स्पेशल ओलिपिक्स भी काकाएं जाते हैं जिनमें ऐसे बच्चे ही हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकार एक हेल्थ के तहत मंदबुद्धि बच्चों के लिए, कितना सोचती है उसका उदाहरण यह है कि प्रथम अमरीकी नहीं तरह से अपनी बात मेटिकल मटिफिकेट बनाते, रखते कन्सेन्शन, सिंह आनंद थे, जो पिछले 16 वर्ष से ऐसे खेल में यशस्म नहीं हैं। इसलिए उनकी सहा-बच्चों की बुद्धि बने हुए हैं जो मंदबुद्धि हैं। ऐसे बच्चों की बात बनाने के लिए प्रयासरत मिलता है, हेत्य इस्पानेस खीम 'निमया' का रख्य में 1500 रुपये प्रतिमाह है।

ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਤੋਸ਼, ਤੁਲਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

## **ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ**

ਜਲੰਧਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਲ)- ਭਾਉਨ ਸਿੱਡੋਰਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਇੰਡੀਆ ਇਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਊਨ ਸਿੱਡੋਰਮ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਉਨ ਸਿੱਡੋਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰੇਖਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੈਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੋਟ ਐਵਾਰਡੀ ਈਸ਼ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਲਡ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸੈਲਡ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁ. ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 280 ਨੁਮਾਇਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ

**ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਂ ਕਾਨਫਰੈਂਸ**



ਭਾਉਨ ਸਿੱਡੋਰਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੈਂਸ 'ਚ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰ ਅਜੀਤ ਹਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਉਨ ਸਿੱਡੋਰਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਡਿਸ਼ਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



# 2 years after Centre passed it, Punjab yet to notify rules under Disabilities Act

ANJU AGNIHOTRI CHABA  
JALANDHAR, JUNE 20

MORE THAN two years after Centre passed Rights of Persons with Disabilities Act in December 2016, Punjab has failed to notify rules under the Act, in turn depriving PWDs several rights under the new law. The Centre has asked state governments across the country to notify rules under the Act.

Sources in the Social Security and Sports Department of Punjab revealed that rules have been drafted and the Act translated in Punjabi.

"Due to delay in issuing the notification, the district-level committees on disability could not be formed and it is hampering the appointment of the state commissioner, advisory committee of the experts in the disability sector and competent courts to decide that whether a child can be separated from his family in the best interest of the child for PWDs," said a senior officer in

**PWDs are suffering on several grounds due to delay in the notification of the rules as neither an 'Equal Opportunity Policy' has been formed nor a nodal officer been appointed in the District Education Office (DEO) to deal with all matters relating to admission of children with disabilities."**

— AMARJIT SINGH ANAND  
EXPERT MEMBER, STATE DIVYANG ADVISORY BOARD

Social Security Department, adding that state fund for PWDs was proposed (amount is not fixed), but could not be implemented as rules under the Act are not notified.

"Expert committee with representation of persons for identification of employment posts reserved for people with disabilities could also not be set

up and also state had yet to issue the notification for increasing reservation quota in employment from three to four per cent for PWDs," said Amarjit Singh Anand, expert member, state Divyang Advisory Board.

He added: "PWDs are suffering on several grounds due to delay in the notification of the rules as neither an 'Equal Opportunity Policy' has been formed nor a nodal officer been appointed in the District Education Office (DEO) to deal with all matters relating to admission of children with disabilities." According to Anand, the quantum of assistance in the poverty alleviation schemes was to be increased by 25 per cent for PWDs, but that too was under process.

He said there is no provision of providing Aadhaar card to bedridden which is basic rights of them.

Anand said that till date Punjab has formulated not state sports policy for special games and there is no cultural policy for the PWDs, which means

that outstanding performers in sports at international events are not given any financial aid by the government.

Punjab Sports Minister Rana Gurmeet Singh Sodhi said that Punjab has sports policy for the disabled and there is no discrimination against them.

Director Sports, Punjab, Dr Amrit Kaur Gill, said that recently a new policy has been made under which Special Olympics, Deaf Olympics and other games related to PWDs are included and the policy would be notified soon.

According to Punjab State Disability Commissioner Kumar Rahul, the notification of rules under RPWD Act are under process.

While Punjab admits that it is in the process of notifying the rules, across the country some 14 states have done the same.

Meanwhile, PWDs are getting disability certificates and state has notified five per cent reservation in allotment of land and other developmental schemes as per Section 37 of the RPwD Act.



## THE QUESTIONS THAT MATTER REGISTERING DIFFERENTLY-ABLED VOTERS

# Over 68k registered, but official says there are many more

**ANJU AGnihotri CHABA**  
JALANDHAR, MARCH 27

FOR THE upcoming Lok Sabha elections, the differently-abled have for the first time been registered as Person with Disability (PWD) voters. But while Punjab has registered 68,551 such voters across all 22 districts, a member of the Diwanjiy Advisory Board believes that the actual number is much higher.

(Data sourced from the office of Punjab chief electoral officer (CEO) shows that 68,551 PWD voters were registered till January 31 this year (see box). Of these, 9,000 have registered so far in Jalandhar and 4,723 in New Delhi district. Awareness campaigns including seminars and programmes under the Systematic Voters Education and

Electoral Participation (SVEP) are being held across the state. Speaking to *The Indian Express*, Amarjit Singh Anand, expert member, state Diwanjiy Advisory Board, said that the number of PWD voters is much more and an extensive awareness drive is required at the grassroots level, especially in rural areas, so more of them register.

Anand further said that according to a 2011 census, Punjab's population was 2.77 crore and the percentage of disabled was 2.62% of the population, which now would have gone up to around 5% of the present population. "Even people with mental disabilities are eligible for voting if they are able to take their own decisions in other activities as there are different categories for that too," he said, adding that though registration of PWD voters ended in



January, 'marking' of such voters will continue till April 19 (which means that disabled voters who have registered as general voters will be marked under the PWD category so they get the facilities).

Accessibility Officer, Jalandhar H. Punishartha said that in order to enable PWD voters to cast their votes during the polls, the administration will provide a pick and drop facility.

PWD voters can either apply by downloading the PWD app on their phones or through their respective Booth Level Officers. District Electoral Officer (DEO) cum Deputy Commissioner, Jalandhar, Varinder Sharma, said that the district administration would ensure provision of wheelchairs, ramps, helpers etc. at all 1,863 booths on polling day – May 19.

*The Indian EXPRESS* TUE, 28 March 2019  
easier editions | [www.indianexpress.com/c/37391315](http://www.indianexpress.com/c/37391315)



# In 3 months, NRI voters quadruple

ANJU AGNIHOTRICHABA  
JALANDHAR, APRIL 30

FROM 393 NRI voters in January, the number of registered NRI voters in Punjab has touched 1521 — a four-fold increase in just three months. This is also the highest number of registered NRI voters in Punjab till date.

The number of NRIs voters has always been remained abysmally low in state ever since they got the right to vote in 2010. The registration of voters in Punjab concluded on Monday. The state votes in the last phase on May 19.

Out of the 1521 NRIs voters, 1159 are males and 362 are female voters. On January 31, there were 264 registered male NRIs voters and 129 females. In 2014, the number of NRIs voters was

169 in Punjab.

"CEO Punjab S Karuna Raju had made NRIs aware in various countries through various programmes including radio programme to register themselves as voters which led to increase the NRI voters this time," said sources in the CEO office. NRIs registered themselves as voters by filling Form 6A which was also available online at the officials website of the EC.

As per the final revision, the total number of voters in Punjab has increased from 2.03 crore to 2.07 crore in past around three months. Also the number of service voters had gone up from 1,02,285, including 1734 females as on January 31 to 1,11,464, including 2370 females on April 29.

The number of Third Gender voters too has increased from 507 to 560.

## PWD voters up 38%

**Chandigarh:** For 2019 Lok Sabha elections, the differently-abled are for the first time being registered as 'Person with Disability' (PWD) voters. Punjab, which had registered 68,551 such voters across all 22 districts as on January 31, has registered almost 38 per cent more such voters as per the final revision.

Data sourced from the office of Punjab Chief Electoral Officer (CEO) shows that 68,551 PWD voters were registered till January 31 this year and on April 29, the final number of these voter is now 1,10,264.

Speaking to The Indian

Express, Amarjit Singh Anand, expert member, state Divyang Advisory Board, said that the number of PWD voters had gone up manifold in past over two months due to an extensive awareness drive the board and and Punjab election officials.

The number of visually impaired voters has gone up from 5814 to 10,144, speech/hearing impaired number has gone up from 4,892 to 7548 voters, locomotor disabled (related to movement of limbs) are now 61,061 against 39,359 and other disabilities voters are now 31,511 voters against 18,486 in January.



l,  
—

go to  
here is

1 hath  
vadde  
lait vi  
5-kilo  
mat-  
votes  
in the

being  
ning,  
after



## Audit of PWD booths reveals unsuitable ramps in rural areas

ANJU AGNIHOTRI CHABA  
JALANDHAR, MAY 1

THE INITIAL state-wide physical audit of polling booths by Divyang Icons — people with disabilities associated with the State Divyang Advisory Board — has revealed that nearly 30 percent of booths in the Punjab designated for Persons With Disability (PWDs) have unsuitable or damaged wheelchair ramps, while others lack western-style toilet seats.

The audit is being conducted under the leadership Divyang Board member Amarjit Singh Anand, who has been appointed the state coordinator for this drive.

The final audit report will be presented to CEO, Punjab on May 4. Most issues have been reported from booths in the state's rural belt.

There are over 10,000 such booths across state designated for disabled persons out of total 23,213 polling stations.

"In the audit report, we have been checking wheelchair ramps, tables inside the booth, light, backup, drinking water, toilets etc.," said a district coordinator from Majha region, adding that around 30 percent booths need to be set right.

In Jalandhar, there are over 800 such booths out of total 1863 polling stations. Jalandhar coordinator Kaushly said that she has 236 booths in Phillaur area under her, out of which 105 she has already audited physically.

**There are over 10,000 such booths across Punjab designated for disabled persons out of total 23,213 polling stations**

"I found that at several booths the ramp was not up to the mark, very steep and it did not begin from the main gate of the polling booth," she said, adding that even there is no English toilet at several booths and at some places toilets seats are high.

These things can be set right as per the needs of the disabled persons," she said.

State coordinator Amarjit Singh Anand said: "This is the first time that people with disabilities have been engaged to do this audit in Punjab. We are getting the support from district administration too and will submit the report by May 4 so that the required rectification on certain places can be done before the polling day."

Indeepit Nandan, who is working as district Hoshiarpur coordinator, said that the election commission has been serious about PWD voters which is encouraging them to come out and vote.

# दिव्यांग बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

## ● पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को शिक्षा विभाग ने किया लागू

जालंधर, 4 मई (माला अग्रवाल) : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया है जिसे सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, इस संबंध में जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी, एडिड या निजी स्कूल दिव्यांग बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है।

गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रहट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जनहित में ओरेशा जारी करते हुए डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग विद्यार्थियों

को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला देने का फैसला सुनाया था। इसके साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स से किसी तरह की भी फीस लेने पर भी रोक लगा दी थी।

कोर्ट के इस फैसले को लागू करते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी एडिड तथा निजी स्कूलों में इसे लागू करने को लेकर पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने में सहयोग देने की जिम्मेदारी दी गई है।

21 प्रकार की दिव्यांगता वाले स्टूडेंट को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा : कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 21 प्रकार से दिव्यांग स्टूडेंट्स को सभी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला देने का प्रावधान तय किया

### फैसला लागू करने के लिए मॉनिटरिंग जरूरी : अमरजीत आनंद

स्टेट दिव्यांगजन इडवाइजरी बोर्ड के एक्सपर्ट मैबर अमरजीत आनंद का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा पहली से 12वीं कक्षा के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने और दाखिला देने से मना न करने का फैसला सराहनीय है। उनका मानना है कि उक्त फैसले को लागू करने के लिए स्कूलों में स्पैशल एजुकेटर होने भी जरूरी है। जबकि हकीकत इससे परे है। स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्पैशल एजुकेटर नहीं है। यही कारण है कि ऐसे बच्चों को स्कूल एडमिशन नहीं देते। उन्होंने आगे बताया कि सी.बी.एस.ई. के नियमों के मुताबिक हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होना जरूरी है जिस पर यह लिखा हो कि इस स्कूल में सभी तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल के पास जितने स्पैशल एजुकेटर हैं उनकी जानकारी भी बोर्ड पर होनी चाहिए। जबकि वास्तव में किसी भी स्कूल के बाहर ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ। इसलिए फैसले को लागू करने के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है।



गया है। इसके साथ ही 21 तरह की स्टूडेंट्स को दाखिले से भी मना न दिव्यांगता की ब्रेणी में आने वाले करने के निर्देश भी दिए हैं।

# दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूलों में तैनात होंगे एजुकेटर

## ◆ भर्ती की प्रक्रिया हुई थुल

जालंधर, 28 जून (माला अग्रवाल): राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग एजुकेटर नियुक्त करेगा। यह एजुकेटर दिव्यांग स्टूडेंट्स को उसकी भाषा तथा जरूरत के मुताबिक पढ़ाई करवाएगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दिव्यांग स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए विभाग द्वारा उक्त कदम उठाया जा रहा है।

गैरततब है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में दिव्यांग स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें शिक्षित करने की व्यवस्था न होने के चलते वह शिक्षा के मूल अधार से दूर ही रहते हैं जिसे लेकर दिव्यांग लोगों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं ने सरकार से इसके लिए कई बार मांग की थी जिसके चलते विभाग ने अब सभी

**सरकारकाफैसला सराहनीय, मॉनिटरिंग भी जरूरी : अमरजीत आनंद**

स्टेट दिव्यांगजन एडवाइजरी बोर्ड के एक्सपर्ट मैंबर अमरजीत आनंद का कहना है कि सरकार का यह फैसला सराहनीय है। लिहाजा, इसके लिए पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी। दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एजुकेटर तैनात करना अहम कड़ी है जिसका संस्था स्वागत करती है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। राइट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट-2016 के अनुसार नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूलों की मान्यता रद्द होने का भी प्रावधान है।



सरकारी स्कूलों में एजुकेटर तैनात करने का फैसला किया है।

**हूमनरिसोर्स डिवैल्पमेंट विभाग  
ने दी मंजूरी**

दिव्यांग स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत व भाषा के मुताबिक शिक्षित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हूमन रिसोर्स डिवैल्पमेंट ने भी शिक्षा विभाग को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत गज्य भर में एजुकेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि जरूरत को देखते हुए इससे पहले भी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ स्पेशल टीचर्स

रखे गए थे। लेकिन वे ज्यादा समय तक सेवाएं नहीं दे पाए। जिसके चलते अब शिक्षा विभाग नियमति रूप से स्पेशल एजुकेटर तैनात करेगा।

**जे.बी.टी व टी.जी.टी स्तर के  
होंगे एजुकेटर**

दिव्यांग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इस पद्धति के जानकारी एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षित करने की पद्धति जे.बी.टी तथा टी.जी.टी में एजुकेटर होना अनिवार्य है। जिससे वे स्टूडेंट्स को 10वीं तक पढ़ाई करवाने में सहायक रहें।

# City not disabled-friendly, say experts

No provision of ramps or wheelchairs at govt buildings, railway station

ANUJIT KAUR

JALANDHAR, PUNJAB

While Jalandhar is on its way to become a smart city, persons with disability here are yet to feel a part of the bigger project as there is no provision of ramps or wheelchairs at the majority of the government buildings, schools and universities.

Anajit Singh Anand, a member of the Punjab State Divyangjan Advisory Board, said the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, makes it mandatory to provide facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations, parking spaces, toilets and ticketing counters so that they could use these with ease. But in reality, the Act remains on paper only.

## ACT REMAINS ON PAPER ONLY

Anajit Singh Anand, a member of the Punjab State Divyangjan Advisory Board, said the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, makes it mandatory to provide facilities for persons with disabilities at bus stops, railway stations, parking spaces, toilets and ticketing counters so that they could use these with ease. But in reality, the Act remains on paper only. Mukesh Aggarwal, general secretary, Chaanan Association for MR Children, said Jalandhar caters to around 80,000 persons with disabilities. However, excluding a few private colleges or universities, no government colleges or schools have facilities for differently abled students.

Expressing displeasure over the sluggishness with which the state and central governments were acting with respect to carrying out audits of the disabled friendliness of buildings, hotels and public places, Anand said: "Be it the district administration, the Municipal Corporation or the railway station, most of the places are not accessible to persons with disabilities."

"Despite having

approached MPs and MLAs a number of times, the project to install escalators and elevators at the city railway station has been hanging fire for the past many years," he said.

As a result, physically challenged passengers are forced to take trains from Phagwara or Jalandhar Cantt as most of the trains, including shatabdi, stop at platform No. 1 there," Anand said.

The Centre's target of making at least 25 per cent of the public transport disabled-friendly has also not been met. There are no single lower-floor buses or smart traffic signals designed for pedestrians with disabilities in the city, Anand said.

Mukesh Aggarwal, general secretary, Chaanan Association for MR Children, said Jalandhar caters to around 80,000 persons with disabilities. However, excluding a few private colleges or universities, no government colleges or schools in the city have facilities for differently abled students.

During examinations, such students are lifted on shoulders and taken to rooms if the examination hall is on upper floors, he said.

# दिव्यांगों के हित में लोक लहर खड़ी करने की जरूरत : चौधरी

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल कल्याण मंत्री अरुणा चौधरी ने सोमवार विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम कर रही जत्थेबदियों, संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की।

उन्होंने ऐसे लोगों के हित में लोक लहर खड़ी करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत जल्द ही दिव्यांग खिलाडियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट

बनाया जा रहा है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर यह यकीनी बनाने के लिए कहा जाएगा कि किसी भी टोल प्लाजा पर विशेष जरूरत वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि पहले पड़ाव में पंजाब के 10 बड़े शहरों का ऑडिट होगा कि वहां महत्वपूर्ण इमारतों में विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं मुहैया हैं या नहीं। इनकी पेंशन में वृद्धि के मुद्दे पर पूर्णतया हमदर्दी से विचार किया जाएगा।



ਚਾਨਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਤ ਕੈਪ ਫੌਰਨ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਸਲਕ ਹਰਸ਼ਕਲ ਕੌਰ ਹੈਪੀ। (ਸੱਜੇ) ਹੈਪੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰੂਣ

## ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਮੌਕਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰੂਣ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ : ਸੇਕਟਰ  
ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ  
ਤਾਂ ਇਹ ਬਚੇ ਵੀ ਆਮ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ  
ਹੁਨਰਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ  
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰਾਵਾਂ ਵਾਰਡ-31 ਦੀ ਕੌਸਲਰ  
ਹਰਾਲਦਰ ਹੈਰੀਪੀ ਨੇ ਨਿਉ ਗੁਰ ਤੌਰ ਬਹੁਲ  
ਨਗਰ ਵਿਖੇ 'ਚਾਨਣ ਸੰਸਥਾ' ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਰੀ  
ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿਕਸਤ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਲਕਾਰੇ  
ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਿਕ ਕੈਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਕਤਿ  
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ  
ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਰ ਹੈਪੀ ਨੇ

### ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ

- 'ਚਾਨਣ ਸੰਸਥਾ' ਦੇ ਸਾਰਾਂ ਕੌਚਿਗ ਕੈਪ  
'ਚਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੰਸਾਨ ਕੌਸਲਕ  
ਕੌਸਲਕ ਹੈਪੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਕੇ ਉਹ ਛੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ  
ਡਾਕਕ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੌਸਲਕ ਹੈਪੀ ਨੇ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਤਿਆਰ  
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ  
ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਲਾ ਅਛੱਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ  
ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ  
ਆਕਾਸ਼ੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  
ਮਲੀਜ ਅਰਜੁਵਲ, ਗੁਰਧੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ,  
ਪਵਲਸੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿੰਕੀ, ਸੁਜੀਤ  
ਕੌਰ ਜੀਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਦਰ ਸਨ।

# ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ

**ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ :** ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰਥਨ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਹਿਆਗੁਪਰ ਵਿਖੇ ਤੇਜ਼ੀਸ਼ੀਸ਼ ਆਘਾ ਕਿਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸਾਂਸ਼ੇਸ਼ੀ ਐਡੋਟੈਨੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਲਵਾਏ ਗਏ ਤੀਸਰੇ 'ਉਮੰਗ 2018' ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਇਆਚਚਰ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸ਼ਮ ਕਰਦਿਆਂ ਓਵਰਾਲ ਸੈਤ੍ਰ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਕਥਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੀਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਲਕਾ ਆਨ੍ਹੀਤ ਕੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਨਵੰਤ ਕੇਰ ਤੋਂ ਕਿਰਜ਼ੋਤ ਕੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਤਿਆਰੀ ਸਟਕਾ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲੇ ਗਾਇਕੀ ਸੂਨੀਅਰ, ਸੈਲੇ ਡਾਸ ਸੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਗਰੂਪ ਡਾਸ ਸੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਾਠੀਵਾਈਡ ਗਰੂਪ ਡਾਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਠਾਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੇ



ਸੁਧਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਾਲ ਟਰਾਈ ਜਿੱਤਣ ਮੌਕੇ ਸਮਰਪਣ ਸਕੂਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਿੱਤ ਕੇਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਸਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਵਹੀਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਪਨਰੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚੌਕੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ' ਗੀਤ 'ਤੇ ਵੀਤੇ ਸੋਕਾਨ ਭਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਸੀਤ ਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹੂਹ ਸਕੂਲ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਦਿੱਤ ਕੇਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿਠਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਲਚੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਝੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਦਰ ਕੌਰ, ਅਵਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

## दिव्यांगों के लिए आशादीप मिड-डे होम का उद्घाटन

अमर उजाला छाग्रे

कुरुक्षेत्र।

उपायुक्त डॉ. एस्पास्स फुलिया ने कहा कि समाज कल्याण के लिए आशादीप संस्था सराहनीय कार्य कर रही है। इस संस्था के योगदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार की संवर्धन समाज के लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है, इसलिए समाज के अन्य लोगों को समाजसेवा के लिए आगे आना चाहिए।

बै शनिवार को खंडी मारकड़ा के पास आशादीप संस्था के मिड-डे होम का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संवेदित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त, विशेषज्ञ सुधा, सुधा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जय भगवान शर्मा, संस्था के अध्यक्ष डॉ. जौधी केसरी, अमरजीत सिंह आनंद, प्रॉफेसर एस्पके गुप्ता ने मिड-डे होम का उद्घाटन किया।

इस दौरान उपायुक्त ने मिड-डे होम के प्रशासनिक व्यक्ति, हास्टल, डेवरी



आशादीप मिड-डे होम का उद्घाटन करते डीसी और विधायक सुभाष नुणा

फार्म, खुंभ फार्म सहित अन्य कक्षों का किया है। इस संस्था को सरकार व अबलोकन किया।

उपायुक्त ने गांवों को चारा भी प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय भगवान शर्मा ने कहा कि दिव्यांग लोगों का पालन-पोषण करना सबसे कठिन कार्य है, इसलिए संस्था के योगदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता है।

विधायक ने कहा-संस्था के लोगों ने दिव्यांगों के लिए संस्थान बनाकर एक सराहनीय कार्य किया

संस्था के सचालक डॉ. जौधी केसरी ने कहा कि इस संस्था में दोनों सुपरवाइजर, 24 घंटे चिकित्सक, मैडिकल सुविधा, शिक्षा, डांस, ड्रामा, संगीत, आर्ट, योग, जिम, हाली सेटर सहित तमाम प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डेवरी, फार्मिंग व सूखा की व्यवस्था के पुरुष इंतजाम किए गए हैं।

इस मौके पर करनैल बाला, नीना, संगीता जैन, संगीता राठी, भास्कर दुबे, जिला परिषद की उपायुक्त परमजीत कश्यप, ल्काल समिति के बाह्य चेयरमैन सोमनाथ सैनी, पार्वद विशाल शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर, सरपंच अंग्रेज पाल कश्यप मौजूद थे।

# Put up boards highlighting rights of special students, schools told

APARNA BANERJI  
TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, APRIL 11

Following the recent instructions of the High Court, the Education Department has asked all schools to put up boards highlighting the rights and privileges of differently abled students at the main gates. They have been given a two-week deadline to follow the instructions.

Schools have also been asked to give free admissions to such students. Besides, education without discrimination, education be made available in the sign language, free helping material, provision of 15 additional minutes after every hour and facility of interpreters and

writers to the students during PSEB exams are among the directions that have been issued to the schools.

All associated, affiliated and aided schools in the state will install boards on their premises mentioning the rights of differently abled students in terms of the provisions of the Disabilities Act 2016. They will also have to put up the contact number of the persons who can be contacted in case of any problem faced by specially abled students.

As per the Act, students with special abilities are supposed to be given admission and free education at schools nearest to them without any discrimination. The directions say specially abled students should be given free books as per their need and arrangements for free helping material also be made available to them.

The instructions further say the schools which have the transport facility should make transport arrangements for their special students. The facility of special toilet and potable water also be made available for the students. Besides, special scholarships be given to stu-

dents with special abilities by the school or board.

Students who want to participate in sports and extracurricular activities, as per their abilities, be allowed to participate without any discrimination.

The Punjab School Education Board has provided various facilities to the special students during examinations, including special type of question paper, facility of

writer, freedom in choice of subject and exemption in the second and third language.

Manish Aggarwal, a teacher at an aided school in the district, said, "The major advantage of these directions is that the students will not face any discrimination now. The provisions of the RTE Act and the Disabilities Act already regulate this, but these guidelines were not being implemented.

We were also getting ramps and proper washrooms constructed. With the implementation of the Act, the guidelines will now be stringently followed. Besides, for the first time, formal declarations have also been made for the interpreters and writers for students, which weren't previously there."

Disability activist Amarjeet Singh Anad said, "Various regulations have been introduced from time to time for special students. These are certainly path-breaking, but all are needed to be implemented."

DEO Satnam Singh said, "Rooms for disabled children in all schools are already present. But with the new instructions, the students' needs and requirements will be taken care of strictly. All facilities mentioned in the letter will be provided to them. The instructions are to be implemented within two weeks. At the district-level, orders will be issued to all schools, including government schools, to implement the instructions from Thursday morning onwards."

JALANDHAR Tribune Thu, 12 April 2018 epaper.tribuneindia.com/c/27799879



निर्देश

पीएसईवी का फैसला एफिलिएटेड स्कूलों पर भी लागू दो सालाह के अंदर सभी स्कूलों को लगाने होंगे डिस्प्ले बोर्ड

## स्कूलों के गेट पर लगेंगे दिव्यांग बच्चों के दाखिले के लिए बोर्ड

पूजा शिंह • जलंधर

अब दिव्यांग बच्चों को दाखिले करवाने के लिए इन-उत्तर अकड़न नहीं पड़ेगा। उन्हें कोई ऐसा स्कूल दूँघने की ज़रूरत नहीं होगी, जहां पर ये शब्द बच्चों को ही पढ़ाया जाता हो। पंजाब स्कूल एजेंसीन बोर्ड की ओर से गश्त के सभी स्कूलों से निर्देश दिए गए हैं कि वे आपने एटोमेंट पर दिव्यांगों के अधिकारों को बालों हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाएं। इसके जरिए सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को दाखिले के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बोर्ड की ओर से सेकेटरी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें साफ लिखा है कि यात्र के सभी स्कूल गेट के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाएं, जिसमें दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में लिखा होगा। इसके साथ ही अगर दिव्यांग बच्चों

डिस्प्ले बोर्ड ना लगाने वाले स्कूलों पर हो कारबाई



पंजाब स्कूल एजेंसीलीटी परिषद्विवरण अमरजीत सिंह आनंद ने कहा कि प्रशासन व डीईओ को सभी से इन अधिकारों का पालन करना चाहिए। अगर कोई भी स्कूल इन निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके द्वितीय सरकार कारबाई करनी चाहिए।

स्टैंडर्ड फोरमेट आने के बाद करेंगे डिस्प्ले : पि. शीरज



डिस्प्ले बोर्ड के प्रशिक्षण शीरज दानोनी ने कहा कि हमें भी यह नोटिफिकेशन भित्ति की इसे डिस्प्ले करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यह चल जाए तो हम भी अपने स्कूल के बाहर डिस्प्ले कर देंगे। हमने सरकार यों तरफ से अनुबूत सशाल एनुक्रेटर भी रखा हुआ है।

बोर्ड का अच्छा कदम, हमने कर दिया डिस्प्ले : पि. रंगारा



एप्लीकेशन परिकल्पना स्कूल आर्सो नगर के ऑफिशियल एप्लीकेशन क्रिएशन केंद्र रंगारा ने कहा कि बोर्ड की ओर से विद्यार्थी व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाने के लिए यह अच्छा कदम है। हम उनके साथ हैं और हमने गेट पर इसे डिस्प्ले भी कर दिया है।

बोर्ड पर दिव्यांगों के अधिकार लिखे होंगे, समस्या आने पर वे किसे काटेवट करेंगे, उस संबंधित व्यक्ति का नवर भी होगा

जापानी। साफ निर्देश है कि स्कूल वाले डिस्प्ले बोर्डों को बिना किये भेंटपाल के दाखिला मिलेगा और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनको मुफ्त बिताये व हैलिंग मरीनियल दिया जाएगा। जिन स्कूलों में अपनी ट्रांस्फोर्मर का प्रबंध है उनकी ओर से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ट्रांस्फोर्मर का प्रबंध होगा। स्कूल की ओर से उन्हें स्कूलरिशिप भी दी जाएगी। सरकार अंत में उन्हें विशेष सुविधाएं जैसे कि हर घंटे पर 15 मिनट का अधिक समय, स्पेशल टाइप प्रश्न पत्र, राइटर की सुविधा अदि दी जाएगी।

# जालंधर के अमरजीत को डाउन्स सिंड्रोम डे अवार्ड

वेदना वालिया वाली, जालंधर

डाउन्स सिंड्रोम इंटरनेशनल संस्था द्वारा जालंधर के अमरजीत सिंह आनंद को डाउन्स सिंड्रोम डे अवार्ड के लिए चुना गया है। वह दिक्षित 21 मार्च को मनाया जाता है। आनंद ने बताया कि उन्हें अवार्ड के बारे में सूचना लंदन रियल संस्था के कार्यालय से प्राप्त पत्र से मिली।

**अमरजीत सिंह आनंद**  
उन्होंने बताया कि विश्व से छह लोगों का चयन स्वयंसेवी एवं व्यवसायी वर्ग में किया गया है, जिनमें वह एकमात्र भारतीय है। उन्हें वह सम्मान पंजाब में गत 18 सालों से डाउन्स सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने व इन स्पेशल बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के अथव प्रयासों के लिए दिया जा रहा है।

'पंजाब डिसएबिलिटी इन्डस्ट्री सुप' के कन्वीनर, 'डाउन्स सिंड्रोम एसोसिएशन, पंजाब' तथा 'चाणग' नामक संघओं के अध्यक्ष और 'स्पेशल ओलंपिक्स भारत' के पंजाब चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट आनंद की अपनी 29 वर्षीया बेटी जसजीत डाउन्स सिंड्रोम से पीड़ित है। वह उसे अपनी प्रेरणा मानते हुए समाज में इन स्पेशल बच्चों को इनके अधिकार बताने और दिलाने की कोशिशें लगातार करते रहे हैं। डाउन्स सिंड्रोम से

- विश्वभर से अवार्ड के लिए छह लोगों का चयन
- डाउन्स सिंड्रोम पीड़ित बेटी से मिली मदद की प्रेरणा

## क्या है डाउन्स सिंड्रोम

डाउन सिंड्रोम एक तरह की मानसिक अस्पस्तता है जो जीन्स में आप बदलावों के कारण होती है। इस स्पष्टरा से ग्रस्त स्पेशल लोगों का आईयू लेवल 50 तक रहता है यानी उनकी मानसिक अवस्था 8-9 साल के बच्चे के समान ही रहती है और नयन-नरस भी दिखाय रहते ही रहते हैं।

पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के एक गुप्त से गुरु रुह उनकी यह मुहिम अब पंजाब में ही दस से अधिक समूहों में तबदील हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि भारत से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के वर्ग में चैन्सैट के एस कहण को यह अवार्ड मिला है। स्पेशल होने के बावजूद यह बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी अग्रणी रहा है। उसने अपनी अक्षमता को हरा कर सक्षम बन अनोखी मिसाल पेश की है।

18.03.2015

धर्म-समाज

## अरविंदर सिंह जिला प्रधान और मनीष महासचिव बने

सिटी रिपोर्टर | जलंधर

विशेष जरूरत वाले बच्चों के अभिभावकों की एक बैठक प्रसिद्ध समाज सेवक अमरजीत सिंह आनंद के निवास स्थान पर ज्ञान प्रसाद जिंदल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्पॉटर्स ऑलिपिक एसोसिएशन की जालंधर इकाई के पुनः गठन का फैसला किया गया।

जिसमें सर्वसम्मति से अरविंदर सिंह को प्रधान और मनीष अग्रवाल को महासचिव चुना गया। अमरजीत सिंह आनंद चेयरमैन, दों कुलदीप सिंह को उपप्रधान और गुरुमुख सिंह को कैशियर मनोनीत किया गया।

महासचिव मनीष अग्रवाल ने बताया कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य स्पेशल बच्चों कि खेलों के प्रति रुचि को जगाना और उनके गुणों को पहचान उसमें निखार लाना है। एसोसिएशन साल में दो बार जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगी और अच्छे खिलाड़ियों को कोचिंग और खेल का समान देगी। जिला प्रधान अरविंदर सिंह ने जताया कि एसोसिएशन के माध्यम से अधिक



जिला ऑलिपिक टीम के वर्कनियुक्त पदाधिकारी अमरजीत सिंह आनंद, मनीष अग्रवाल और अन्य।

से अधिक फैंटस को जोड़ा जायेगा और विशेष जरूरत वाले बच्चों को एक यंत्र प्रदान किया जायेगा ताकि वह अपने अधिकारों को पहचान सकें। सभी स्पेशल बच्चों के फैंटस, स्पेशल स्कूल, एन जी ओ के प्रतिनिधि इस एसोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं।

एसोसिएशन के प्रदेश उपप्रधान अमरजीत सिंह आनंद ने बताया कि जिला इकाई गठित

होने के साथ जलंधर कर खिलाड़ियों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। क्योंकि जलंधर में कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहे हैं और जिले में कई काबिल खिलाड़ी है। संगठन की कमी के कारण खिलाड़ी संस्कारी स्तर पर मिलने वाले लाभ और सुविधाओं से भी विचित रहते थे।

## गणतंत्र दिवस समारोह में 45 स्पेशल बच्चे सम्मानित

जागरण संवाददाता, जालंधर : स्टेट स्पेशल ओलंपिक खेलों (लुधियाना - 2013) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 45 स्पेशल बच्चों को गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में मंत्री सरवण सिंह फिल्लौर ने सम्मानित किया।

इस मौके पर सरवण सिंह फिल्लौर ने बच्चों के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा भी की। सम्मानित होने वाले बच्चों में ऐश्वर्या वैसिफिक स्पेशल ओलंपिक आरट्रेनिंग में पदक जीतने वाले दो बच्चे भी शामिल हैं।

सम्मानित होने वाले बच्चों में बज्र अब्बा आशा स्कूल जालंधर कैट से गुप्तीत कौर, कार्तिक, शिव कुमार, आनिथ कुमार, टीपू व हरसिमरनजीत तथा सेट जासफ कान्हेट स्पेशल स्कूल से अमरदीप, साहिल अग्रवाल, मनुहर भूषण, साहिल बद्धण, सागर कालिया, गौरव, शिवम, अर्जुन, सिम्मी, दमन, इदवीर, अभिषेक व गंताष शामिल थे। इसके अलावा रेडफोन प्रयास स्पेशल स्कूल से अजय, वेद मुकेश, प्रीत, चंदन, सदीप व वरिद्ध तथा उड़ान स्पेशल स्कूल से जसप्रीत सिंह, इश्विंदर सिंह, विवेक अग्रवाल, गहताशा



गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किए गए स्पेशल बच्चों के साथ कैबिनेट मंत्री सरवण सिंह फिल्लौर। साथ हैं डीसी वरुण रूजम, अमरजीत सिंह आनंद व अन्य। अरेहा, नवजोत सिंह, आकाशदीप, पौली, अखिल पांडे, नवजीत ओबराय, नितिन कलसी, वासु, जसमीत सिंह, हरप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, हरीश रौशनी व पवन शामिल थे।

## धर्म.समाज

### पहली बार जिले के स्पेशल बच्चों का सम्मान



जालंधर | गणत्रौंकियता समिति के द्वारा पहली बार मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सरवण सिंह फिल्मोर ने जिले के 47 स्पेशल बच्चों को सम्मानित किया। चानग एकोसिएशन के अमरजीत आनंद के प्रयासों से बच्चों का सम्मान हुआ। इस दौरान इंटरनेशनल पैदा औलीपेक्षा में जीतने वाले बच्चे इश्विंदर के पिता डॉ. कुलवीप सिंह, रेडकॉस रक्तूल के प्रिसिपल पितांबर, सैट जोसाक की अकुराया, आर्मी रक्तूल की भगुराणा, उड़ान रेपेशल रक्तूल की प्रिसिपल नेहा शाही गौजूद रहीं।

## जल्दियाँ/आम-पाम

दोरवाच, 30 जनवरी, 2014

10



ਵਸਾਰੇ ਟੇ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਏ ਆਪਾ ਸਪੈਸਲ ਸਕੂਲ, ਸੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸਲ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਿਆਮ ਰੈਂਡ ਕਰਮ ਸਪੈਸਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਸਪੈਸਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 43 ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਗਠਤੱਤਰ ਦਿਵਸ ਮੰਨੇ ਕੇਵਾਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੈਰ ਤੋਂ ਸੱਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਚੰਕ ਤੋਂ ਆਪਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ

## इश्विंदर और विवेक का स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स ने किया सम्मान



आस्ट्रेलिया में स्पेशल बच्चों के ओलिंपिक में जीतने वाले इश्विंदर सिंह व विवेक अग्रवाल को चैक देते अमरजीत सिंह आनंद व अन्य।

-भारकर

भारकर न्यूज़ | जालंधर

ऑस्ट्रेलिया में हुई स्पेशल ओलिंपिक की 100 मीटर रेस में अलग-अलग आयुवर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जालंधर के स्पेशल बच्चे इश्विंदर सिंह और नकोदर के विवेक को चानण एसोसिएशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पेरेंट्स ने सम्मानित किया। एसोसिएशन में 300 मेंबर हैं, और यह स्पेशल बच्चों को पेरेंट्स ने मिलकर बनाई है।

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमरजीत आनंद ने कहा कि इन स्पेशल बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाकर इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। दुख की जात है कि स्पोर्ट्स विभाग की ओर से कोई भी

इन स्पेशल बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आया। यह दोनों बच्चे अपने-अपने पेरेंट्स के खर्च पर ऑस्ट्रेलिया गए। यहाँ तक कि इस उपलब्धि के बाद न ही सरकार और न ही स्पोर्ट्स विभाग से कोई आगे आया। बतौर प्रधान, पंजाब डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन की ओर से इश्विंदर जो कि डाउन सिंड्रोम से ही ग्रस्त है को 50 हजार रुपए का चैक देकर इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया और वहीं विवेक को 11 हजार रुपए का चैक देकर इस जीत के लिए सम्मान दिया गया। आनंद ने बताया कि उन्हें यह फंड, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पंजाब एसोसिएशन को जारी किया गया था।

# Mentally challenged woman shifted to protective home

APARNA BANERJI

CURRENT NEWS SERVICE

JALANDHAR, JANUARY 10

The abandoned, mentally challenged woman, who began receiving treatment at the Civil Hospital as per orders issued by the Chief Judicial Magistrate (CJM) on Saturday, was on Wednesday ordered to be shifted to Nari Niketan.

While earlier, there was a speculation that the woman might be shifted to Amritsar, based on the report and recommendations of doctors at the Civil Hospital, the Chief Judicial Magistrate on Wednesday ordered the woman to be shifted to Nari Niketan.

However, the woman, now identified as Gurpreet Kaur, was ultimately taken to the State Women Protective Home at Basti Gujan here yesterday, after the Nari Niketan authorities refused

CJM (a copy of which is with The Tribune) issued here yesterday, stated, "Medical certificate of Gurpreet Kaur received. As per the same, she is suffering from mania and psychotic features and as per the same she needs further treatment. It has been advised by the doctor that she can be shifted to Nari Niketan, Jalandhar, as she needs follow-up treatment."

"Disability activist Amarjit Singh Anand, who first began the task to bring justice to the woman, said while the court orders were for Nari Niketan, the Niketan authorities, citing the reason that they only adopt children up to the age of 16 years, refused to take the mentally ill woman."

Anand, along with ASI Harjit Singh, GRP Jalandhar, and women staff then approached the State Pro-

requesting them to accept Gurpreet Kaur.

While the home's in charge agreed to accept the patient, she has asked for the order to be amended in the next two days, so that Gurpreet can be kept there.

Notably, the statement of Gurpreet's father Mohan Singh, a resident of Harnamdaspura locality in Jalandhar, was also recorded and taken into consideration before the aforesaid order was issued.

Mohan Singh confirmed that Gurpreet was "not of good mental health".

While Mohan Singh's wife has also died, he stated Gurpreet had also tried leaving his house various times earlier. While Gurpreet was married, her husband had also died.

Mohan Singh stated he would be unable to look after his daughter due to

# ENOUGH WITH WAIT: POLICE

APARNA BANERJI

TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, OCTOBER 27

This one is straight out of a comic gag.

Even as people usually crib for lack of proper services, this is one situation where the services are waiting to be availed with baited breath, but no one's willing to avail them.

The Special Olympics scenario in the district has fallen prey to inactivity, miscommunication, mudslinging and missed opportunities.

The Tribune had brought the issue of special schools not availing the services of a police coach (arranged by the police department) to train their students ahead of the special Olympics a week ago.

A week later, the coach is still waiting for a (any) student to turn up, even as livid police officials moot suspending the option, with just six days to go for the Olympics (two of them being holidays).

Meanwhile, the situation has turned ugly with some schools in a denial mode even

- | Not a single child sent to special police coach
- | Police moot suspending special coach option
- | Prayas School says children being trained already
- | Udaan School says no one informed them
- | Disability activist disagrees

eludes students.

When contacted today, one of the schools made a U-turn on its previous statement, claiming its students were being coached for the past 15 days. Another said they were never informed about the coach, in turn inviting the ire of activist Amarjit Singh Anand who says he went the extra mile for them.

Ranjana Bansal, honorary secretary, Red Cross Hospital Welfare Society, had said a week ago that she had sent applications to the DC and Deputy Commissioner of Police for a means of transport to ferry children to the police lines ground, where the training had to be held.

While she had earlier said the coaching of children would begin from Monday when the means of transport is made available, she said today, "Our children are

days before Monday. One of our own teachers has been coaching them and coaches had also been called from the DAV College to provide training to them."

One of Prayas School staff members said the school teacher coaching them for the past 17 to 18 years was good enough to have gotten them medals.

Meenu Shahi, Principal, Udaan School said, "No one informed us that a coach is available. Why wouldn't we train our children if a coach is there? In fact, Mr Anand had told us about arranging for a coach. But when we enquired again about a month ago, he told us no coach was available. Now with just a few days left for the games, and with holidays in between, sending children for the coaching does not make sense."

Amarjit Anand, however,

missioner of Police and then the ADCP. Would I go through all this trouble just not to inform the school later? The Udaan School principal had shown me a list of 13 children that they wanted a special coach for. When I later informed them about the coach, they had said they do not have a means of transport to send children."

ACP Jasbir Singh Rai said, "Ever since we made the coach available, I haven't received a single call on the issue, nor has anyone come to us with their special children. An inspector rank office, a former athletics player, had been made available to coach children at the police lines ground. We have waited long enough for the children to turn up. I will be making enquiries from the coach again on the matter. We will be suspending the option soon if there is no response."

The Special Olympics will be held on November 3, 4 and 5. Both Prayas School and Udaan Schools said they would be sending their school children to the

# अच्छे समाज की सृजना के लिए बच्चों को उच्च विद्या प्रदान करवाना जरूरी : कलगीधर ट्रस्ट

संत अतर सिंह की याद में सालाना समागम जालंधर में 6 और 7 को



प्रैस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अमनदीप सिंह ट्रस्टी, साथ हैं परमिंद्रपाल सिंह खालसा, जगजीत सिंह गाबा, दविंद्र सिंह आनंद, कंवलजीत सिंह व अन्य।

जालंधर, 2 अप्रैल (चावला) : कलगीधर ट्रस्ट बड़ साहिब के ट्रस्टी अमनदीप सिंह दिल्ली और गुरप्रताप सिंह ने कहा कि अच्छे समाज की सृजना के लिए बच्चों को उच्च विद्या प्रदान करवाना जरूरी है। ट्रस्ट द्वारा पूरे भारत में 500 अकैडमियां खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये अकैडमियां उत्तर भारत के उन देहाती क्षेत्रों में खोली जाएंगी जहां शिक्षा की सख्त जरूरत है।

प्रैस कांफ्रेंस में ट्रस्टियों ने कहा कि कई इलाकों में नौजवान पीढ़ी नशे जैसी भयानक बुराई का सामना कर रही है जिस कारण इन इलाकों में उच्च विद्या प्रदान करवाना एक बड़ी जरूरत है। उत्तर भारत में 130 अकैडमियां खोली गई हैं जिनमें 70,000 बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। अकाल अकैडमी के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक चेतना पैदा करने में अहम योगदान दिया जा रहा है और नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता रैलियां निकाली

जा रही हैं। वहीं सिख सेवक सोसायटी इंटरनैशनल के प्रधान परमिंद्रपाल सिंह खालसा तथा जगजीत सिंह गाबा ने बताया कि कलगीधर ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित व संत अतर सिंह की याद में सालाना समागम गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर में 6 और 7 अप्रैल को करवाया जा रहा है जिसमें सचखंड श्री दरबार साहिब के हजूरी कीर्तनी जत्थों के अलावा बाबा इकबाल सिंह बड़ साहिब, कथा वाचक तथा विद्वान संगतों की गुरबाणी कीर्तन और गुरमति विचारों से निहाल करेंगे।

इस मौके पर दविंद्र सिंह आनंद, डा. परमजीत सिंह, मनजीत सिंह ठुकराल, कंवलजीत सिंह सैक्रेटरी, छनबीर सिंह, ईशर सिंह, रजिंद्र सिंह बेदी, अमरजीत सिंह आनंद, उजागर सिंह, ज्ञानी गुरमीत सिंह, संतोख सिंह दिल्ली पेंट आदि उपस्थित थे।

Government of Punjab  
Department of Social Security, Women & Child Development  
(Disability Branch)

NOTIFICATION

No.01/01/17-3DC/155&563/

Dated, Chandigarh 22/8/19

In continuation of the notification issued vide No. 01/01/17-3DC/1277271/1, dated 20/07/2018, the Governor of Punjab, in exercise of the powers conferred upon him under Section 66(2)(d) of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, is pleased to nominate the following members to the State Advisory Board on Disability:

1. Shri Angad Singh, MLA  
II.No. 157, V.Saloh,  
Tehsil and District S.B.S.Nagar.
2. Shri Dalvir Singh Goldy, MLA  
Ward No.8A, 141 Guru Teg Bahadur Nagar, Dhuri,  
Tehsil Dhuri, District Sangrur.
3. Smt. Satkar Kaur, MLA  
V&P.O. Shakoor,  
Tehsil & District Ferozepur.

Place: Chandigarh  
Date: 02.08.2019

Rajiv P. Srivastava  
Principal Secretary, Government of Punjab  
Department of Social Security, Women &  
Child Development.

Endstt No.01/01/17-3DC/

Dated, Chandigarh,

A copy is forwarded to the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001, for information only.

— Sar —  
Deputy Secretary

No.01/01/17-3DC/

Dated, Chandigarh:

A copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Principal Secretary/Chief Minister, Punjab, Chandigarh.
2. The Chief Secretary to the Government of Punjab, Chandigarh.
3. The Principal Secretary/Chief Minister, Punjab, Chandigarh.
4. All Additional Chief Secretaries/Financial Commissioners/Principal Secretaries/Administrative Secretaries to the Government of Punjab.
5. The Commissioner for Persons with Disabilities, Punjab, Chandigarh.
6. The Accountant General (A&E) Punjab, Chandigarh.
7. The Accountant General (Audit) Punjab, Chandigarh.
8. The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
9. All Heads of Departments, Government of Punjab.
10. All Commissioners of Divisions.